there will be European position also, along with the other European countries. How these positions will harmonise into a common position of the West remains to be seen.

Uniformity in Education

+

*481. SHRI *RAM SWARUP RAM:

SHRI SATYAGOPAL MISRA:

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce common system of education for every citizen of India by banning all public schools and making education a Central subject, prescribing one syllabus througout the country and giving equal opportunities to the students for competitive examinations conducted by U.P.S.C.;

(b) if so, details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND SOCAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) to (c). A statement is laid on the Table of Lok Sabha.

Statement

Government does not propose to make education a Central subject. Although education is a concurrent subject, education, particularly school education, is still primarily the responnsibility of the State Governments.

Curriculum and Syllabus at the school level are prescribed by the State Governments and the Boards of Secondary Education. At the collegiate level, these are prescribed by the Universities concerned. Expert advice on the subject is in favour of decentralising curriculum and syllabus.

It has been the effort of Government to develop a uniorm structure of education viz., 10+2+3 as also to develop model curricula so that, within a uniform structure, comparable standards can be maintained. Opportunities provided for mutal consultations in forums like Conference of Boards of Secondary Education (COBSE), Central Advisory Board of Education (CABE), Conference of Ministers of Education, Conference of Vice-Chancellors, All India Council of Technical Education (AICTE) etc. are utilised towards this end.

In regard to competitive examinations conducted by the UPSC, equal opportunities are available to all who fulfill the relevant conditions of eligibility.

It is Government's stated policy to equalise educational opportunity. Towards this end, it has been Government's endeavour to open as many schools as possible to bring educational opportunities within the reach of all.

So far as "Public" schools, which, in effect, are private schools, are concerned because of certain Constitutional safeguards, it is not possible to ban them.

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की ओर से जो जवाब आया है उसको मैं ने बहुत गम्भीरता से देखा है, एक एक शब्द को पढ़ा है, इसमें उन्होंने लिखा है कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है फिर भी हम इसको केन्द्र के अधीन नहीं ला सकते हैं। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हम अभी तक अपनी शिक्षा को प्रयोगवाद में ले जा रहे हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं कि सवाल पूछिए।

श्री राम स्वरूप राम : सरकार कभी टन प्लस टू प्लस 3 की ओर ले जाती है और कभी टेन प्लस वन प्लस टू की ओर ले जाती है। देश के लिए शिक्षा का बहुत महत्व होता है और इस पर देश का भविष्य निर्भर है। अभी उस का प्रयोगवाद चल रहा है और अभी हम एक नीति तय नहीं पा कर रहे हैं कि सारे देश में किस तरह की शिक्षा चले, किस तरह के पाठ्यक्रम सेकेन्डरी स्कूलों के लिए, प्राइमरी स्कूलों के लिए और युनिवर्सिटियों के लिये हों। बिहार में एक तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही है और यू० पी० में दूसरी तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही है। इसलिए एक तरह का समान स्तर डेवलप नहीं हो रहा है सारे देश में इस कारण जो राष्ट्रीय एकता है उस में कहीं न कहीं और कुछ न कुछ विखंडता नजर आ रही है और एकमात्र शिक्षा इस के लिए दोषी है। इस संदर्भ में इस की अहमियत को समझते हुए, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश में एक ही स्तर की शिक्षा चलाना चाहती है और उस को को-आर्डिनेट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी जो यह सुनिश्चित करे कि सारे देश में एक ही पाठ्यक्रम हो और एक ही स्तर की पढ़ाई सभी वर्गों में हो ?

SHRIMATI SHEILA KAUL: School Education is primarily the business of the States. Every State makes its own syllabi. Though we have gone on structural basis on 10 plus 2 plus 3 pattern as the hon. Member has just now mentioned, this we have done to ensure that there is a basis for solid elementary education. The NCERT, in consultation with the various States has worked out a Minimum Learning in regard to Mathematics and general Continunm from classes 1 to 5. This is in regard to Mathematics and general environmental conditions and to provide for variety of local specifis curricula to suit the needs of the diverse problems of children. This we have done. But to say that we should have one pattern of education throughout India would not be the right thing in the general outlook of the country where such lot of variety exists. The people living in West Bengal have their own way of dressing and eating and all that which is very different from the people of the Punjab for instance. So, such variety exists. If we take the different States, they have got their own identity which we like to keep. But there are certain things as I mentioned which we have got to provide. We have given a structure to the education in which children of all the classes 1 to 5 can learn and grow as one.

अध्यक्ष महोदय : दरअसल में आप के नाम से ही इन्होंने कुछ लिया है ऐसा लगता है। आगे भी राम, पीछे भी राम, कौनसा स्वरूप है राम का। इसी तरीके से इन्होंने एजुकेशन को कानकेन्ट सबजेक्ट बना कर किया है।

श्री राम स्वरूप राम : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि शैक्षणिक अवसर को समान बनाना सरकार की एक घोषित नीति है। हमारी शिक्षा का स्तर एक हो, समान अवसर सभी को मिले चाहे वह सामान्य जनता हो और चाहे वह विशिष्ठ जनता हो लेकिन दोषपूर्ण शिक्षा की वजह से हमारे यहां दो तरह की, दोहरी शिक्षा प्रणाली चलने की वजह से एक ही समय में दो स्टैन्डर्ड के लोग पैदा हो गये। आप जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए वही-गुरु जी की पाठशाला है, वही चटाई पर बैठ कर वे पढ़ते हैं और उन्हें कोई पाठ्यक्रम नहीं मिलता पढ़ने के लिए और न रोशनी मिल पाती है और न किताबें मिल पाती हैं। कितना गरीब यह मुल्क है।

अध्यक्ष महोदय : आप छोटा सवाल कीजिए ।

श्री राम स्वरूप राम : इस सभी के संदर्भ में ही यह भूमिका है। इसको अगर नहीं कहा जाएगा तो कैसे समझा जाएगा ।

हुजूर आप भी गांव में रहते हैं जब तक हमारा लक्ष्य समान स्तर की शिक्षा सभी को देने का नहीं होगा तो कैसे लोग आगे आयेंगे । आज हमारी शिक्षा दो केटेगरी में बंट गई है । इसमें से एक केटेगरी का वर्ग काफी डेवलप कर गया है । उसमें बिजनेसमेन हैं, उच्च श्रेणी के पदों पर काम करने वाले हैं । यह सब हमारी दोहरी शिक्षा नीति की वजह से हो रहा है । उच्च पदों पर काम करने वालों का भी स्वार्थ डवलप कर गया है । इस सब के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली दोषी है । जब हमारी नीति समान स्तर की शिक्षा देने की है तो क्या सरकार दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर के सभी गांवों के स्कूलों को एक स्टेण्डर्ड पर लाएगी । यदि नहीं तो क्या सरकार सभी पब्लिक स्कूलों को बंद करेगी जिससे कि शिक्षा का समान स्तर हो सके ?

क्या सरकार इस बात की अहमियत को समझते हुए सभी स्कूलों को एक ही स्टेण्डर्ड पर लाना चाहती है और पब्लिक स्कूलों को बंद करने का विचार रखती है ? चूंकि एक दूसरे प्रश्न के जवाब में यह कहा गया था कि विचार नहीं है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा को एक स्टेण्डर्ड पर लाने के लिए क्या सरकार देश के सभी शिक्षा संस्थानों लोअर स्कूल से ले कर यूनिवर्सिटीज तक—को एक स्तर पर लाने के लिए कोई क्रमबद्ध योजना बनाने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप सारे सवाल का वजन खोते जा रहे हैं।

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, यह बताना जरूरी है ।

SHRIMATI SHEILA KAUL: The expression public school is a misnomer because the schools that are supposed to be public are private schools. They are owned either by societies or by associations and they are not Government schools. So, to say that these public schools should be stopped

श्री दौलत राम सारण : केन्द्रीय सरकार उन्हें अनुदान देती है । यह गलत कह रही हैं ।

श्रीमती शीला कौल : अगर मुझको जवाब देने का मौका मिल जाए तो आपकी तृप्ति हो जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आप तृप्ति कीजिए ।

श्रीमती शीला कौल : अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो कैसे मालूम होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया को जवाब देने दीजिए ।

श्रीमती शीला कौल : हमारे यहां जो पब्लिक स्कूल हैं वे प्राइवेट लोग खुद चलाते हैं । माना कि इनको सरकार कुछ मदद देती है लेकिन पब्लिक स्कूलों में वीकर सेक्शंस के बच्चों के लिए 25 फीसदी जगहें होती हैं और इन सैक्शंस के जो बच्चे होशियार होते है उनको इनमें पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिलता है । (व्यवधान)

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, हमारा जवाब नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : वे एक बात पूछना चाहते हैं कि उनके हितों की रक्षा करने हेतु आप क्या कदम उठायेंगी । यह जो ड्युल एजूकेशन है—जिसके पास पैसा है वह तो पब्लिक स्कूल में माडल स्कूल में, कान्वेन्ट स्कूल में पढ़ता है और जिसके पास पैसा नहीं है, मेरे जैसे आदमी के पास, वह बोरी दबा कर पढ़ने जाता है ; यह जो स्कूलों में डिफ्रेंस है जिसकी वजह से इन्टरव्यू और कम्पीटिशन में बोरी ले कर पढ़ने वाला मुकाबला नहीं कर सकता उस विषय में आप क्या करना चाहते हैं, यह जवाब दीजिए ।

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर मैंने अभी कहा है कि जो काबिल बच्चे होते हैं, इनके लिए एक इम्तहान है, जो स्टेट लेवल पर होता है ।. . . (व्यवधान)

SHRI SATYAGOPAL MISRA: Mr. Speaker, Sir, the language and the spirit of the question is not the same which I wanted to ask. On the contrary it is carrying the idea just opposite. Le me clear it. We want that Education should come under the State List. Education should not even be a Concurrent Subject. Education is a very vital subject. Everybody should acknowledge it. I must point out that the range of the question is so wide that it needs a full discussion. For national, emotional and intellectual integration it is necessary that a comprehensive education policy should be framed for the whole of the country.

Now, Sir, I want to have some clarifications from the Hon. Minister. According to the Central Government, what should be the language or the languages which should be taught in Primary Schools i.e., upto Class V standard? Private schools are creating discrimination among the people. So, what is the proposal of the Central Government to overcome the constitutional hurdles to ban those private schools?

MR. SPEAKER: How many questions are you asking?

SHRI SATYAGOPAL MISRA: There is a wide range of questions. What step is the Government taking or proposes to take to make education free to children upto the age of 14 years? This has been guaranteed under the Constitution aim this was aimed to be achieved by the year 1960.

MR. SPEAKER: My God, it is catalogue it is not a question.

SHRI SATYAGOPAL MISRA: Is Government ready to accept the proposal to spend 10 per cent of the Central Budget for the education of the children of our country? If not, why not?

MR. SPEAKER: This is not the supplementary type. Supplementaries are short, pungent and incisive.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, steps have taken for free education for children till the age of 14 years. It is only the private schools which charge fees. But the schools run by the Government are free for children upto the age of 14 years. And, Sir, he has asked me so many questions.

MR. SPEAKER: You cannot ask all question like this.

SHRI SATYAGOPAL MISRA: Language Sir. Sir in a primary school what is the language policy? Sir, here they are saying one thing and in the countryside they are saying another thing.

SHRIMATI SHEILA KAUL: It is the regional language.. The mother tongue is to be taught to the child.

SHRI SATYAGOPAL MISRA: Only the mother tongue or something else?

SHRIMATI SHEILA KAUL: At the Primary level education is through mother tongue.

श्री **विलास मुत्तेमवार** : पिछले दिनों कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नैनीताल के एक पब्लिक स्कूल में एक छात्र ने जब हिन्दी बोल दी थी तो उसकी वजह से उसके टीचर ने उसका अपमान किया था, उसको मारा था और क्या यह सही नहीं है कि इस सार्वजनिक अपमान के कारण उस लडके ने आत्महत्या कर ली थी ? उस किशोर की आत्महत्या का यह जो सवाल है उसकी तरफ क्या शिक्षा मंत्रालय का ध्यान गया है ? क्या उसको इसकी जानकारी है और अगर है तो उस दिशा में उरकार ने क्या किया है । अंग्रेज तो यहां से चले गए हैं लेकिन आज भी जो लोग अपनी क्लास में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं उनके साथ ऐसा बरताव किया जाए तो क्या यह एक गंभीर मामला नहीं हो जाता है और क्या इस की तरफ शिक्षा मंत्रालय का ध्यान गया है ?

MR. SPEAKER: It does not flow from this question. This is irrelevant. We have drawn attention to it already under 377. Now Mr. Jagdish Tytler.

SHRI JAGDISH TYTLER: When my friend Ram Swaroop Ji just mentioned about the closing of public schools, you found that there was quite an approval from the Treasury as well as Opposition benches. I, as a person who runs a school, am surprised. Of the people are sitting here, the children of over 70 per cent of them are studying in public schools.

MR. SPEAKER: You might have under rated it. It might be 90 per cent.

SHRI JAGDISH TYTLER: Here are the Members who send their sons to these public schools in spite of the ideology they may have, or of the ideology of their parties. I am not saying that public schools should or should not remain. It is for the Government to decide. We will all accept Government's decision. But is the public school really harming the national stream, and is the public school really harming the cause of national integration? On this my pointed question is this. (*Interruptions*) Don't say that you are the people who send letters to me to admit your children (*Interruptions*)

MR. SPEAKER Order, please.

SHRI JAGDISH TYTLER: My pointed question is this: what faults and strengths have been found in the present running of various types of schools which are competing in the education of children? Will the removal of such schools not also remove the healthy and clearly competitive spirit among the educationists for the betterment of education and educational facilities? what steps is Government taking to bring their own schools in competition with the public schools?

SHRIMATI SHEILA KAUL: We have shown the direction in this manner by creating a few Central Schools. And I believe they are welcome by the public, because there is so much demand to open more Central Schools. That shows that he direction shown by the opening of Central Schools is welcomed by the public.

श्री रामावतार शास्त्री : : क्या यह सच है कि देश के कई शिक्षक संघों ने मांग की है कि भारत के सभी स्कूलों के लिए एक ही पाठयक्रम होना चाहिये, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए? अगर की है तो एक ही पाठ्यक्रम बनाने के बारे में सरकार ने अब तक क्या प्रयास किया है और उसका क्या नतीजा निकला है?

श्रीमती शीला कौल : अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था। यह कहा गया था कि कामन शिक्षा प्रणाली बननी चाहिये और उसके उत्तर में मैंने इसका जिक्र किया था। कनसलटेटिव कमेटी जो पार्लियमेंट की है उस में भी यह सवाल उठा था। तब भी यह कहा गया था कि एक पता नहीं होनी चाहिये। मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं वे नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बराबरी हो। वे चाहते हैं कि उनकी अपनी जो लोकल बातें है, लोकल ज्योगराफी है, लोकल उनका रहन सहन है, उनका तरीका है, उस सब की उनके बच्चों को जानकारी हो बनिसबत इसके कि दूर दो हजार मील पर क्या हो रहा है। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मंत्री महोदया ने बताया कि शिक्षा को केन्द्रीय विषय बनाने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। पर में पूछना चाहती हूं कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय तो है ही और विभिन्नता में एकता ही हमारा उद्देश्य है. जैसा राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में कहा है कि कम से कम यूनीवर्सिटी ऐजूकेशन केन्द्रीय विषय होना ही चाहिये। इसलिये मैं पूछना चाहती हूं कि आज जो विभिन्नता और ग्रुपिज्म यूनीवर्सिटी ऐजूकेशन में हो रही है क्या उसे दूर करने के लिये मंत्री महोदया यह विचार रखती हैं कि कम से कम वाइस-चांसलर, जैसा कि राधाकृष्णन आयोग ने भी कहा है, की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अधिकार में हो तथा अन्य

जो प्रोफेसर और रीडर्स हैं उनकी नियुक्ति यू०जी०सी० के माध्यम से हो क्या इस प्रकार का आप विचार रखती हैं ?

श्रीमती शीला कौल : जो अभी जिक्र हुआ है हमारी कनकरेंट लिस्ट ऐजूकेशन की है और कोआर्डिनेशन ऐनश्योर करने के लिये तथा स्टेन्डर्ड बनाए रखने के लिये ही हम उसमें दखल देना चाहते हैं । साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि जो हमारी नेशनल इम्पोर्टेन्स की चीज है, नेशनल इंटेग्रेशन उसको प्रोमोट कर सकें, इस काम को अपने नीचे ले सकें जिससे कनकरेंसी आफ ऐजूकेशन को हम पूरा कर सकें। इसके अलावा हम किसी तरह का इंटरफीयरेंस नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि जो हमारे नेशनल इंस्टीटयूशन्स हैं उनको बढ़ायें इसलिये कनकरेंसी में लिया है। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि जो एक स्टेट का विषय है शिक्षा का उसमें किसी प्रकार का दखल दें ।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा महत्व का विषय है और इस पर दो मिनट में कोई विचार नहीं हो सकता। आज जाति से ले कर धर्म, सम्प्रदायों के स्कूल देश में चल रहे हैं उसमें किस प्रकार से राष्ट्रीयता प्राप्त कर सकते हैं, अनुशासन बना कर रख सकते हैं, और 90 प्रतिशत गांवों में रहने वाले लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से एकरूपता ग्रहण कर सकते हैं। यही कारण है कि हम कहीं के नहीं रहते । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसी राष्ट्रीय नीति तैयार कर रहे हैं जिसके अन्दर राष्ट्रीयता और राष्ट्र हमारा जिन्दा रहे ताकि विद्यार्थियों में एकता हो। ऐसा कोई प्रयास है ?

श्रीमती शीला कौल : मैंने अभी कहा है कि टाइप आफ ऐजूकेशन जो है वह विभिन्नता को देखते हुए एक सी नहीं हो सकती।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: In view of the fact that education is supremely important in the life of a society, in view of the fact also that we have some excellent recommendations by the committees like Mudaliar Committee, Radhakrishnan Committee and also the Kothari Commission, in spite of all those recommendations, we do not have any national policy on education. You have come to power. Sufficient time has elapsed. Are you going to formulate a national policy on education and provide guidelines to the States so that we can have some standard policy on education?

SHRIMATI SHEILA KAUL: I wish to remind the hon. member that we have already laid on the Table of the House all the recommendations made by the different Committees about which he had just now mentioned.

Prevention of Mental Retardation

+

*481-A. SHRI K. LAKKAPPA:
SHRI D. M. PUTTE GOWDA:

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a team of Scientists at the Indian Institute of Science, Bangalore has achieved a major breakthrough in the detection and prevention of several forms of mental retardation;

(b) if so, the deails thereof;

(c) whether according to leading scientists of the Institue, now mental retardation in new-born babies can be detected and effectively treated; and

(d) the time by which this new achievement will be put into operation in the hospitals throughout the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). It has been established that when detected early, inborn errors of metabolism leading to mental retardation, can be treated by suitable dietary therapy. In the screening programme developed at